(घ) इस व्यापार को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) कालीनों तथा दरियों का निर्यात भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लि० द्वारा किया जाता है जो भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० का अनुषंगी निगम है ।

(ख) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम का इन मदों का निर्यात व्यापार मुख्यतः पश्चिम जर्मनी, स्विटजरलैंड, आस्ट्रिया, नीदरलैंड, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, सं० रा० अमरीका तथा जापान के साथ होता है ।

(ग) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों में किये गये इन मदों के निर्यात निम्नलिखित हैं :

(करोड़ रु० में)

| वर्ष | कालीन तथा दरियां |
|---|---|
| 1973–74 . . | 174 |
| 1974–75 . . | 330 |
| 1975–76 . . | 668 |

(घ) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम पिछले दो वर्षों से देश से हाथ द्वारा गांठे डालकर बनाए गए ऊनी कालीनों का अकेला सबसे बड़ा निर्यातक है । हैम्बर्ग के मुक्त पत्तन में निगम द्वारा कालीन भांडागार डिपो खोला गया है । डिपो की सेवाएं भारत के समस्त कालीन निर्यातक समुदाय को उपलब्ध हैं ।

निगम नए डिजाइनों तथा रंग-योजनाओं के विकास का काम भी करता है । यह निरन्तर बाजार आसूचना तथा अनुसंधान में लगा रहता है ताकि भारतीय कालीन की मांग बनी रहे तथा उसका विस्तार हो । उत्पाद विकास निगम के कार्यकलापों का अभिन्न अंग है । निगम विनिर्माताओं को तकनीकी सलाह भी देता है ।

सरकार ने निगम से जम्मू तथा कश्मीर में 23 कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिये कहा है । इनमें से 16 केन्द्र खोले जा चुके हैं शेष केन्द्र चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खोल दिए जाएंगे । यथासमय ये प्रशिक्षण केन्द्र उत्पादन केन्द्र बन जाएंगे ।

जहां तक दरियों का सम्बन्ध है, निगम अपने डिजाइन परामर्शदाताओं से परामर्श करके रंग योजनाएं प्राप्त करता है और डिजाइन प्लेटें बनवाता है ताकि अपरम्परागत डिजाइन विकसित किये जा सकें ।

प्राइवेट निर्यातकों की तरह निगम को भी कई प्रकार के सामान्य प्रोत्साहन सरकार से उपलब्ध हैं । व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा उत्पादन का आधार मजबूत बनाया जा रहा है । आशा है कि इसके अन्तर्गत अगले तीन वर्षों में 30,000 बुनकर प्रशिक्षित हो जाएंगे ।

**On-The-Spot Study teams to suggest Steps to make Rural Banks More Effective**

*144. SHRI D. D. DESAI : Will the Minister of REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether Government propose to constitute on-the-spot study teams to suggest steps to make rural banks more effective;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) whether primary credit societies will be involved in working out credit needs of rural areas ?

THE MINISTER OF STATE IN-CHARGE OF THE DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE) : (a) and (b). Yes, Sir. This is proposed to be done by constituting a spearhead team consisting of three to five members for each of the Regional Rural Banks. These teams will make survey of the areas with growth potential for promotion of Farmers' Service Societies and prepare bankable projects for consideration.

(c) Primary Cooperative Credit Societies properly strengthened and re-organised into viable multi-purpose cooperative societies or Farmers' Service Societies are expected to be the main agencies for meeting the credit needs of rural areas. They may be financed either by a co-operative bank or commercial/Regional Rural Bank.

**Balance of Trade**

*147. SHRI ARVIND M. PATEL : SHRI VEKARIA :

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) The balance of trade position till date; and

(b) the extent of improvement registered, if any, during the last one year?

THE MINISTER OF COMMERCE (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA) : (a) and (b). The deficit in India's balance of trade increased marginally to Rs. 1216 crores in 1975-76 as compared with Rs. 1190 crores in 1974-75. However, there was a surplus balance of Rs. 88·5 crores during the first quarter (April-June) of 1976-77 as against an adverse balance of Rs. 311·4 crores during the corresponding period of last year.



**राजस्थान से ऊन का निर्यात**

*149. श्री लालजी भाई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में राजस्थान से विदेशों को कितनी ऊन का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : ऊन निर्यातों के आंकड़े राज्यवार अथवा क्षेत्रवार नहीं रखे जाते बल्कि अखिल भारत के आधार पर रखे जाते हैं ।

**Implementation of recommendation of Banking Commission Regarding Discretionary Powers of Managers of Nationalised Banks**

*150. SHRI P. GANGADEB : Will the Minister of REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether Banking Commission's recommendation regarding giving of discretionary powers to the nationalised banks' managers has been implemented; and

(b) The steps being taken to tighten the loose-ends of the administration in the banks?

THE MINISTER OF STATE IN-CHARGE OF THE DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE) : (a) Yes, Sir.

(b) Public sector banks have taken several steps to tighten the loose ends of administration, prominent among these are :

(i) decentralisation of decision making authority and effective delegation of powers, improved loan appraisal machinery, and accelerated disposal of work through special arear clearance drives;

(ii) ensuring of punctuality, cleanliness, discipline, activisation of vigilance